Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 27-11-2006

Participants : Rawat Prof. Rasa Singh

>

Title : Need to include more districts of Rajasthan under National Rural Employment Guarantee Scheme.

प्रो. रासा सिंह रावत : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं कि 01.02.2006 से कार्यान्वित राट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के प्रथम चरण में देश के 600 जिलों में से केवल 200 जिलों का चयन किया गया था। इसमें राजस्थान के 32 जिलों में से केवल 6 जिलों का चयन किया गया। ऐसा मालूम पड़ा है कि इस चयन का आधार राज्य की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी, प्रति व्यक्ति आय, कृाि उत्पादकता, मजदूरी आदि हैं। इस आधार पर राजस्थान के साथ घोर अन्याय किया गया है। राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों की कुल आबादी 29.8 प्रतिशत है जबकि आन्ध्र प्रदेश में 22.8 प्रतिशत और महाराट्र में 19.1 प्रतिशत है। र्वा 2003-04 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 15,485 रुपये थी जबकि आन्ध्र प्रदेश में 20,757 रुपये और महाराट्र में 29204 रुपये है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान के 32 जिलों में से केवल 6 जिलों का चयन किया गया है जबकि आन्ध्र प्रदेश के 23 जिलों से 13 और महाराट्र के 32 जिलों में से 12 जिलों का चयन राट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत किया गया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूगा कि राट्रीय रोज़गार गारंटी योजना के अंतर्गत विस्तार करके राजस्थान के और जिलों को शामिल किया जाये तथा उसके साथ हुये अन्याय का समाधान किया जाये।